अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी, देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी, बंद रहेंगे सिनेमा-स्कूल

बिहार विधानसभा चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- कोरोना और बाढ़ के कारण इलेक्शन नहीं रोका जा सकता

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में मेट्रो ट्रेन, धार्मिक कार्यक्रमों और राजनीतिक की सशर्त मिली इजाजत, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद

युवराज
NEWS TODAY update
न्यूज़ टुडे
RNI:- BIHHIN05409
राष्ट्रीय हिन्दी पाक्षिक
आपकी आवाज़
www.newstodayupdate.in

वर्ष : 06 अंक : 16+2 तिथि : 31 अगस्त 2020 मूल्य : नि:शुल्क प्रधान संपादक : डा. राजेश अस्थाना – 9471005272, 8210595830

email: newstodaymth@gmail.com website : newstodayupdate.in

अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी, देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी, बंद रहेंगे कोचिंग-सिनेमा-स्कूल

न्यूज टुडे एक्सक्लूसिव :

डा. राजेश अस्थाना,
एडिटर इन चीफ,

केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आइये जानते हैं कि अनलॉक–4 के लिए जारी गाइडलाइंस में किन सुविधाओं को मिली है इजाजत और किन पर बरकरार रखी गई है पाबंदियां...

दिल्ली मेट्रो भी चलेगी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो सात सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के संचालन को लेकर विस्तृत एओपी जारी की जाएगी। इसके बाद आम लोगों के लिए मेट्रो के इस्तमाल संबंधी निर्देश भी जारी होंगे...

सामूहिक कार्यक्रमों को शर्तों के साथ इजाजत

दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।

लॉकडाउन के लिए नए निर्देश

अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

आने जाने पर कोई रोक नहीं

राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।

ओपन-एयर थिएटर खोलने की इजाजत

आगामी 21 सितंबर से खुली हवा वाले थिएटरों (ओपन–एयर थिएटर को छोड़कर) को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल–कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस अवधि तक ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

टीचिंग स्टाफ को बुलाने की परमशिन

नई गाइड लाइन में स्कूल कॉलेजों को भले ही बंद रखने को कहा गया है लेकिन राज्य और केंद्र शासित सरकारें ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कार्यों के लिए 50 फीसद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकती हैं। यही नहीं गाइड लाइन में यह भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट अपने शिक्षकों से मिलने जा सकते हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी

सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा।

बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह

पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

इन गतिविधियों को इजाजत नहीं

1– सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे
2– केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं
3– पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी केवले चुनिंदा ट्रेनों के संचालन को इजाजत

ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षणों को इजाजत

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन एवं भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजिकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षणों की मंजूरी भी दी गई है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को राहत

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप एवं उनके प्रशिक्षण दाताओं को भी कार्य शुरू करने को मंजूरी दी गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में मेट्रो ट्रेन, धार्मिक कार्यक्रमों और राजनीतिक की सशर्त मिली इजाजत, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद

ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक–4 के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। इन दिशा–निर्देशों के तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर–शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली–काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

दिशा–निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक–4 के लिए जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा–निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- कोरोना और बाढ़ के कारण इलेक्शन नहीं रोका जा सकता

आशीष राज,
स्थानीय संपादक,

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को तब तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया था जब तक कि राज्य कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त घोषित नहीं हो जाता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा. 'अभी चुनाव आयोग ने चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है. ऐसे में अभी से कोई आकलन करना सही नहीं होगा.'

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि कोरोना के मद्देनजर चुनाव टाल दिया जाए. बिहार में इस साल के अंत तक विधान सभा चुनाव होने हैं. कोर्ट ने कहा, 'कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकता. चुनाव आयोग हर बात का ध्यान रख कर चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा.'

इससे पहले कोविड–19 महामारी के मद्देनजर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव को टालने की मांग के बीच निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने रविवार को बताया था कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर होगा. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा. ऐसे संकेत हैं कि अक्टूबर–नवंबर के बीच किसी समय चुनाव हो सकते हैं. निर्वाचन आयोग (ईसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया, 'बिहार का चुनाव निश्चित तौर पर समय पर होगा.' राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने महामारी के समय चुनाव कराने के औचित्य पर सवाल उठाया है. राजग की घटक लोक जनशक्ति पार्टी ने महामारी के मद्देनजर चुनाव टालने का अनुरोध किया है.

राकांपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी जैसे कुछ अन्य दलों ने भी चुनाव टालने की मांग की है. महामारी के दौरान बिहार विधानसभा का चुनाव और कुछ अन्य उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए सुझाव पर राजनीतिक दलों ने हाल में अपना जवाब दिया था. पिछले सप्ताह आयोग ने महामारी के दौरान चुनाव और उपचुनाव कराने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश को सामने रखा था. चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के मुताबिक मतदाताओं को मतदान के दौरान ग्लव्स दिए जाएंगे. पृथक–वास में रहने वाले कोविड–19 के मरीजों को मतदान के दिन अंतिम समय में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.

कोविड–19 निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं के लिए अलग से दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे. मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी.

रजि० कार्यालय :
अष्ठाना निवास,
मठिया जिरात,
मोतिहारी-845401
समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें-
9471005272

Yuvaraj Media & Entertainment
बिहार विधानसभा चुनाव में डिजीटल प्रचार के लिए संपर्क करें:
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

मुख्यमंत्री नीतीश ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- लोग भड़काएंगे, पर याद रखिएगा

चुनावी हलचल

डा. राजेश अस्थाना,
एडिटर इन चीफ,
न्यूज टुडे मीडिया समूह

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसको काम की ना जानकारी है और ना समझ, वे उल्टा–पुल्टा बोलते रहते हैं। कुछ तो गांवों में जाकर लोगों को भड़काएंगे भी। पर, सबलोग याद रखिएगा। पहले क्या स्थिति थी और अब कितने काम हुए हैं। पहले गर्मी में भी गांव के रास्ते में कीचड़ दिखते थे।

सीएम नीतीश ने कहा कि अब राज्य के एक लाख 14 हजार, 621 वार्डों में से एक लाख 13 हजार 209 वार्डों में हर घर तक पक्की गली और नाली बन गई है। शेष वार्डों में भी शीघ्र निर्माण पूरा हो जाएगा। कुछ जगहों पर पेवर ब्लॉक भी लगे हैं। यह अच्छी चीज है, इससे बारिश का पानी जमीन के नीचे जाता है, जिससे भू–जल स्तर मेंटन में मदद मिलेगी। कहा कि कुछ लोग तो दायें–बायें करेंगे हीं। शराबबंदी से भी कुछ लोग नाराज है। पर, हमलोग अपना काम करते हैं।

बिहार के 58 हजार वार्ड समितियों को हर माह मिलेंगे 2000 रुपये

हर घर नल का जल निश्चय योजना के रख–रखाव के लिए 58 हजार 500 वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समितियों को अब दो–दो हजार हर माह, अर्थात 24 हजार सालाना मिलेंगे। साथ ही, इस योजना के बेहतर संचालन के लिए हर वार्ड में चयनित अनुरक्षक को 500 की जगह एक हजार महीना बतौर रिटेनर शुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। एक अक्टूबर के प्रभाव से यह लागू होगा। पहले पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्डों की समितियों को एक हजार व अनुरक्षक को 500 रुपये महीना मिलता था।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन दोनों निश्चय हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की नाली और गली की 33 हजार 716 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2009 और 2010 में अपनी यात्रा के दौरान खगड़िया, मुंगेर, भोजपुर आदि क्षेत्रों में आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड प्रभावित पानी पीने से बीमार हुए लोगों को मैंने देखा था। ये दृश्य मैं कभी भूलता नहीं हूं। तभी से मेरे मन में था कि कैसे सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाये। वर्ष 2015 में मैंने हर घर नल का जल निश्चय योजना की शुरुआत की। शुरू में योजनाओं के क्रियान्वनय में थोड़ी दिक्कतें आईं, पर अंततः इसे सफल किया गया। अब लोगों के घरों में पानी को शुद्धकर आपूर्ति की जा रही है।

लोगों को निरंतर लाभ मिलता रहे, सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 72 प्रतिशत से अधिक वार्डों में नल–जल पूरी कर ली गई है। शेष वार्डों में यह काम अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ लोगों को निरंतर मिलता रहे यह संबंधित विभागों के अधिकारी सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों की भी यह जिम्मेदारी है कि इसका संचालन बेहतर ढंग से कराएं। लोगों से आग्रह भी किया कि नल–जल योजना के तहत आपूर्ति हो रहे पानी का उपयोग पीने और भोजन पकाने में ही करें। अन्य कार्य के लिए कुओं और चापाकल के पानी का उपयोग करें। कुओं का जीर्णोद्धार और चापाकलों की मरम्मति का भी कार्य किया जा रहा है। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और वे खुले में शौच ना करें तो 90 प्रतिशत बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा।

उत्कृष्ट 38 खिलाड़ियों एवं 9 प्रशिक्षकों को प्रशस्ती पत्र से सम्मानित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा- खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का अनुकरण कर ओलंपिक में बनाएं अपनी जगह

अच्छी पहल

सम्राट, संवाददाता

देश के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जिले के युवा खिलाड़ी अनुकरण करें और लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनकी यादों में ओलंपिक में अपनी जगह बनाने का प्रयास करें। उक्त बातें आज जिलाधिकारी एसके अशोक ने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 पर समाहरणालय स्थित राधाकृष्णन भवन में सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही।

डीएम राष्ट्रीय खेल दिवस पर उप मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी चंपारण जिला के 38 उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा खेल संघों के प्रशिक्षकों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने क्रिकेट के 5, एथलेटिक्स के 5, फुटबॉल के 6, ताइक्वांडो के एक, बॉल बैडमिंटन के चार, बॉक्सिंग के खिलाड़ियों में केतन कुमार द्विवेदी सहित सात, कैरम के एक खिलाड़ी को एवं शैलेन्द्र मिश्रा बाबा समेत 9 प्रशिक्षकों को प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। मौके पर सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, प्रशासनिक पदाधिकारी जिला खेल पदाधिकारी मौजूद थे।

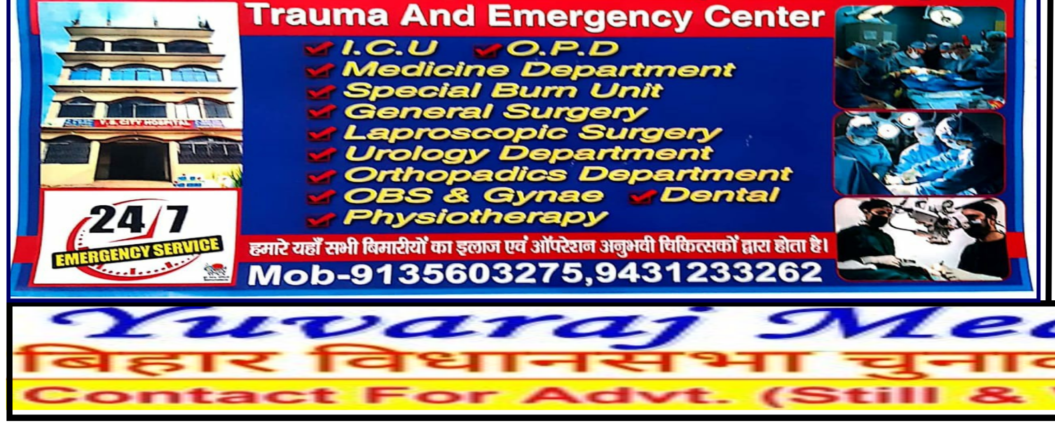

जांच में रिश्वतखोरी और कार्य में लापरवाही पाई गई सही पाए जाने पर घोड़ासहन अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी दीनबंधु पांडेय को डीएम ने किया बर्खास्त

कार्रवाई

रिंकू गिरी,
संवाददाता

पूर्वीचंपारण जिले के घोड़ासहन अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी दीनबंधु पांडेय को जांच अधिकारियों के प्रतिवेदन में आरोपों की सत्यता उजागर होने के उपरांत जिलाधिकारी एसके अशोक ने बर्खास्तगी का आदेश दिया है। जारी पत्र में डीएम ने बताया है कि निलंबित उक्त राजस्व कर्मचारी पर रिश्वतखोरी, सरकारी कार्य में लापरवाही, कर्तव्यहीनता समेत अन्य लगे आरोप सत्य पाए गए हैं।

जबकि, कारणपृच्छा में मिले जवाब संतोषप्रद ही नहीं मनगढंत साबित हुए है। जिससे दीनबंधु पांडेय को रिश्वत मांगने, लेने और कार्य में लापरवाह होने के मामले में दोषी करार देते हुए सरकारी सेवा नियमावली 1946– 3(!)!! आदि के तहत सरकारी सेवा कार्य से बर्खास्तगी का आदेश दिया है। जिसके बाद वे किसी तरह के नियोजन माध्यम से सरकारी सेवा देने से भी वंचित होंगे। डीएम ने इस संबंध में पत्र जारी कर स्थापना विभाग समेत समस्त संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है।

बिहार पुलिस मुख्यालय ने 50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने का आदेश लिया वापस

कार्रवाई

रिंकू गिरी,
संवाददाता

बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से 23 अगस्त को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेल एसपी को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक उन्हें ऐसे पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा करनी थी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है और शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं। लेकिन अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने उस आदेश को वापस कर लिया है।

मालूम हो कि इस आदेश का बिहार पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने सरकार एवं पुलिस मुख्यालय को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी और आईजी मुख्यालय नैयर हसनैन खान से मुलाकत कर इस आदेश पर आपत्ति जतायी थी।लेकिन अब बिहार सैन्य पुलिस समादेष्टा कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और कहा गया है कि पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

समय का फेर, राजद से जुड़ते ही अपने घर से बेघर हुए श्याम रजक, सरकारी आवास करना पड़ा खाली

कार्रवाई

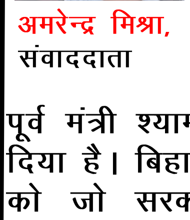

अमरेन्द्र मिश्रा,
संवाददाता

पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आज अपना सरकारी घर खाली कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री होने की वजह से श्याम रजक को जो सरकारी बंगला और सुविधाओं मिली थी उसको उन्होंने छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मैंने सरकारी घर और सुविधाएं छोड़ दी हैं। श्याम रजक कभी जेडीयू के कद्दावर नेता हुआ करते थे। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री और फुलवारी शरीफ से विधायक थे।

श्याम रजक पाला बदलने वाले हैं इसको भांपने के बाद जेडीयू ने उनको पार्टी से निकाल दिया था और सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट से भी बर्खास्त कर दिया था। श्याम रजक ने इसके अगले दिन विधायिकी से भी इस्तीफा दे दिया था और आरजेडी का दामन थाम लिया था। वे इससे पहले भी लंबे वक्त के आरजेडी में रहे हैं और राबड़ी शासनकाल में मंत्री भी रहे हैं। इन दिनों श्याम रजक तेजस्वी यादव के खास सिपाहसलारों में से एक हैं।

मुजफ्फरपुर में जननी बाल सुरक्षा घोटाला मामले में अंतरिम प्रतिवेदन में दोषी पाए गए प्रखण्ड लेखापाल बर्खास्त

सम्राट,
संवाददाता

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुशहरी में जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत की गई अनियमितता के संबंध में अंतरिम प्रतिवेदन में दोषी पाए गए लेखा पाल पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। जांच दल द्वारा अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर आरोप सत्य पाया गया है, जिसके आधार पर प्रखंड लेखा प्रबंधक, अवधेश कुमार की संलिप्तता सामने आई है जिन्हें बर्खास्त (सेवा मुक्त) कर दिया गया है।

सीएसपी संचालक पर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु बैंक को लिखा गया है। बैंक अपने स्तर से जांच कर कार्रवाई करेगा। साथ ही पुलिस द्वारा भी सीएसपी संचालक की भूमिका की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य प्रबंधक की भी लापरवाही सामने आई है। जिसके आधार पर स्वास्थ्य प्रबंधक पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका 50प्रतिशत मानदेय स्थगित किया गया है। अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई उनपर सुनिश्चित की जाएगी।

इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। उनके जवाब के बाद स्पष्ट हुआ कि चुकि उन्हीं के द्वारा अनुमा. दन किया गया था जिसे जांच दल द्वारा लापरवाही माना गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करने का आदेश हुआ है।

अभी तक जांचोपरांत जो भी राशि सामने आई है और आगे भी जांच के उपरांत जो राशि सामने आएगी उसकी वसूली के लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सत्यापन के लिए टीम गठित हुई है, जिसका प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंतिम जांच प्रतिवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विधि सम्मत एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेडल्स के साथ सड़क पर उतरे बिहार के खिलाड़ी, 2015 से नियुक्ति नहीं होने पर जताया रोष

चेतावनी

आशीष राज,
स्थानीय संपादक,

हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन सरकार की ओर से कई खिलाड़ियों को सम्मानित किये जाने और कुछ न कुछ नयी घोषणाएं करने की भी परंपरा है. परन्तु बिहार के खिलाड़ी सड़कों पर उतर आए और अपने अधिकार मांगे. दरअसल प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की बदहाल स्थिति है. खिलाड़ियों की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति 2015 से बंद है. सरकार की इसी बेरुखी के विरोध में खेल दिवस पर सूबे के खिलाड़ियों ने राजधानी पटना में प्रदर्शन किया गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहे तक विरोध मार्च निकाला.

आक्रोशित खिलाड़ियों ने अपने मेडलों के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की. बिहार प्लेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर वर्ष सभी खेलों से पांच खिलाड़ियों को नौकरी देंगे, लेकिन 2014–15 में जितने भी खिलाड़ियों ने आवेदन दिया उनमें से आधे से अधिक को नौकरी नहीं मिली. नियुक्ति प्रक्रिया ही बंद है. ये जिन अधिकारियों ने किया है उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

उन्होंने कहा कि बिहार में खेलों और खिलाड़ियों की स्थिति काफी दयनीय है. अधिकारियों की वजह से नियुक्ति बंद है. अधिकारी मौज कर रहे हैं और खिलाड़ी सड़कों पर हैं. आखिर भूखे पेट खिलाड़ी मेडल कहां से लाएंगे. बिहार में खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये सिर्फ अधिकारियों की वजह से है. मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं खिलाड़ियों को नौकरी देंगे तो 2014–15 की नियुक्ति क्यों बंद है. आज खेल दिवस है सरकार आज फिर लम्बे चौड़े वादे करेगी.

Yuvaraj Media & Entertainment
बिहार विधानसभा चुनाव में डिजीटल प्रचार के लिए संपर्क करें:
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण के अद्यतन स्थिति की हुई समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव ने कहा- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैंपलिंग लक्ष्य के अनुरूप करें

कोरोना स्पेशल

सम्राट, संवाददाता

बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड–19 के संक्रमण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान संक्रमण से बचाव के लिए सैंपलिंग लक्ष्य के अनुरूप करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराएं। जो व्यक्ति ऐंटीजन टेस्ट में सिंप्टोमेटिक पाए जाते हैं, उनका आरटी पीसीआर करावाएं। वहीं उन्होंने कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस टेस्ट करने का निर्देश दिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी एसके अशोक ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य को संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहायक समाहर्ता सिविल सर्जन एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गोदी मीडिया पर कसा शिकंजा, सिविल सर्विसेज में कथित रूप से मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित सुदर्शन न्यूज च ै न ल का शो हुआ बैन

कार्रवाई

विकाश शर्मा, संवाददाता

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सिविल सर्विसेज में कथित रूप से "मुस्लिमों की घुसपैठ" पर आधारित सुदर्शन न्यूज चौनल के ट्रेलर के प्रसारण पर रोक लगा दी है। जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ ने तत्काल सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।

याचिकाकर्ताओं ने सुदर्शन न्यूज पर "बिंदास बोल" नामक कार्यक्रम के प्रस्तावित प्रसारण को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, जिसे आज रात 8 बजे प्रसारित किया जाना है, जिसमें कथित तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इसके पूर्व छात्रों और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने, हमला करने और उकसाने वाली सामग्री शामिल है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने पत्रकार सुरेश चव्हाणके के शो का ट्रेलर देखा है, और यह आरोप लगाया है कि श्री चव्हाणके जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और मानहानि की है। कथित तौर पर, शो में दावा किया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की सफलता "मुसलमानों द्वारा सिविल सेवा में घुसपैठ करने की साजिश" का प्रतिनिधित्व करती है।

NEWS TODAY Update newstodayupdate.in | युवराज न्यूज़ टुडे आपकी आवाज | Yuvaraj Media & Entertainment
Web News Portal: www.newstodayupdate.in | राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका | An Ideal Film Production
बस एक क्लिक कीजिए
देश दुनिया की खबर के साथ अपनी खबर भी देखिए
www.newstodayupdate.in
A Fast Growing Web News Portal
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

युवराज मीडिया एंड एंटरटेण्मेंट की घोषित चम्पारण की पावन धरती पर बन रही भव्य वेब सीरिज एवं फीचर फिल्म की शुटिंग शीघ्र शुरू होगी ।
निर्माता:9471005272

मुख्यमंत्री नीतीश के विकास मॉडल का गवाह बना बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड का मॉडल एवं बिहार का आदर्श ग्राम पंचायत बिहारी बिगहा

न्यूज टुडे खोज खबर

आशीष राज, स्थानीय संपादक,

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के करीब 8 हजार पंचायतो मे विभिन्न विकास योजनाओ की लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल–जल योजना समेत अन्य योजनाओ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शुभारंभ किया, तब बाढ़ के पंडारक प्रखंड का मॉडल एवं बिहार का आदर्श ग्राम पंचायत बिहारी बिगहा भी इसका गवाह बना।

मुख्यमंत्री श्रीकुमार द्वारा हर घर नल–जल योजनाओं के लोकार्पण किये जाने के अवसर पर बिहारी विगहा पंचायत को दुल्हन की तरह सजाया गया और बहां भव्य समारोह आयोजित किया गया। पंचायत भवन में आयोजित भव्य समारोह में हजारो की संख्या मे पंचायत के लोग मौजूद होकर मुख्यमंत्री के विकास योजनाओं के शुभारंभ समारोह को टेली विजन के माध्यम से देखा व सुना।

इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें शामिल कलाकारों ने बिहार मे नीतीश सरकार में हुये काम काज और विकास कार्यो की रुप रेखा कला के माध्यम से प्रदर्शित किया।इस दौरान पंचायत भवन मे आयोजित कार्यक्रम का संयोजन करते हुये पूर्व मुखिया व जिला पार्षद पति रणवीर सिंह पंकज ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से किया वायदा को निभाया। पांच साल मे सात निश्चयऔर हर घर नल का जल योजनाआमआदमी के काम में आया है।

सरकार ने इसे शत प्रतिशत जमीन पर उतार कर लोगों की जरुरत को पूरा किया है। उन्होने कहा की बिहारी विगहा एक मॉडल पंचायत है,जहा सरकार की योजनाओ को शत–प्रतिशत पूरा किया गया है। वही सात निश्चय के तहत की योजनाओ को भी पूरा किया गया है। इस मौके पर आयोजित समारोह के दौरान पूर्व मुखिया ने विभिन्न गांवों से आये करीब एक हजार लोगो के बींच राशन पैकेट का वितरण किया। जिसमें चावल, आंटा, दाल समेत अन्य खाद्य सामग्री शामिल है। वही लोगो के बींच मास्क व सेनेटाइजर भी दिया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी विपुल भरद्वाज, शिक्षाविद चन्द्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह, चन्देश्वर प्रसाद गांधी, पारसनाथ समेत अन्य लोग भी मौजुद थे।

ब्रावो फाउंडेशन ने जिले के सभी थानों, सर्किल व डीएसपी कार्यालय के लिए उपलब्ध कराया ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन

अनुकरणीय पहल

सम्राट, संवाददाता

कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहाँ रोज कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है वही इस महामारी के रोकथाम के लिए ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडेय ने कोरोना वारियर्स पुलिसकर्मियो के दर्द को समझा और पूर्वी चंपारण के प्रत्येक थानों, सर्किल व डी एस पी कार्यालयों के लिए तिरसठ (63)ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन लगाने के लिए सभी मशीनों को पुलिस पदाधिकारी लाइन डी एस पी रमेश कुमार साव को सुपुर्द किया गया जिसे श्री साव ने हरी झंडी दिखाकर रव. ाना किया और फाउंडेशन के टेक्नीशियन टीम के द्वारा लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
बताते चले कि लॉक डाउन के शुरुआत के द्वितीय चरण से ही ब्रावो फाउंडेशन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पदाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, जिले के मंदिरों, कॉलेजों व और कई अन्य जगहों पर मशीन लगाकर कोरोना से बचाव के लिए पहल कर लोगों को जागरूक किया था इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को चम्पारण के लाल राकेश पांडेय ने इतनी बड़ी संख्या में मशीन उपलब्ध कराकर पुलिशकर्मियो को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर निश्चित रूप से दिन रात लोगों की सेवा में जुटे कोरोना वारियर्स का हौसला बढ़ाया है।
मौके पर पुलिस लाइन डी एस पी रमेश कुमार साव ने राकेश पांडेय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी थानों, सर्किल व डी एस पी कार्यालयों के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन उपलब्ध कराकर बहुत बड़ी मदद की है और इस अनोखे प्रयास के लिए मैं सराहना करता हूँ।
वही लंदन से दुरभाष पर ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडेय ने बताया कि इस तरह का प्रयास ब्रावो फाउंडेशन लगातार चम्पारण में करता रहा है और आगे भी संकट की हर घड़ी में फाउंडेशन चम्पारणवासियों के मदद व सहयोग के लिए तैयार रहेगा और हरसंभव मदद करेगा।
इस मौके पर फाउंडेशन के प्रवक्ता शैलेन्द्र मिश्र बाबा, राजेश रंजन, रवि रंजन कुमार, विवेक सिंह, आयुष रंजन, जितेन्द्र ठाकुर, आयुष्मान, पिंटू सिंह,उपेन्द्र पटेल, वीरेंद्र प्रसाद साहू इत्यादि मौजूद थे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, इस्तीफे की अटकलें तेज

सियासी हलचल

डा. राजेश अस्थाना,
एडिटर इन चीफ,
न्यूज टुडे मीडिया समूह

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से 'महाराष्ट्र सरकार में मंत्री' वाली बात हटा ली है। जिसके बाद से उनके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे के साथ कथित कनेक्शन की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि एक हालिया इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने आदित्य ठाकरे के साथ किसी भी तरह से संबंध होने की बात से साफ इंकार किया है। आदित्य ठाकरे अभी महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी उठा रहे हैं।

आदित्य ठाकरे का अभी जो ट्विटर बायो है, उसमें उन्हें युवा सेना का अध्यक्ष, मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबाल एसोसिएशन का अध्यक्ष बताया गया है। बीते दिनों अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के भूमिपूजन के बाद शिवसेना ने मुंबई में जगह जगह होर्डिंग लगाए थे। इन होर्डिंग्स में भी आदित्य ठाकरे की तस्वीर गायब थी, जिसे लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही थी। उद्धव ठाकरे की अयोध्या यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे भी उनके साथ थे, ऐसे में जब राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पार्टी के होर्डिंग लगे तो उनमें आदित्य ठाकरे का ना होना कई लोगों को अखरा था।

दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे का नाम खूब चर्चा में बना हुआ है। जिससे आदित्य ठाकरे की छवि थोड़ी धूमिल हुई है। वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण राणे ने राजपूत मामले की जांच में 'किसी को बचाने' की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि अपने ऊपर उठ रहे सवालों पर आदित्य ठाकरे ने सफाई दी है और कहा है कि 'महाराष्ट्र सरकार की सफलता और लोकप्रियता से परेशान होकर राजपूत की मौत को लेकर गंदी राजनीति की जा रही है और ठाकरे परिवार को बेवजह इसमें खींचा जा रहा है।'

बता दें कि आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाला संगठन युवा सेना इन दिनों NEET JEE परीक्षाएं स्थगित करने की मांग को लेकर भी चर्चा में है। इसे लेकर युवा सेना द्वारा कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। आदित्य ठाकरे ने इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है।

मोतिहारी के छतौनी में इलेक्ट्रॉनिक दुकान चोरी कांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश, लूट की दो लैपटॉप सहित मामले में दो गिरफ्तार

उपलब्धि

संतोष राऊत
न्यूज टुडे,

मोतिहारी शहर के छतौनी थाना क्षेत्र स्थित धर्मसमाज रोड के गणपति ट्रेडर्स नामक इलेक्ट्रनिक दुकान से 15 लाख रुपये मूल्य के चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर छतौनी के खोदानगर निवासी सागिर उर्फ प्यारे व साजिद उर्फ बाबू बताया गया है।

इस संबंध में एसपी नवीन चन्द्र झा ने बताया कि गिरफ्तार चोर के पास से चोरी की गई दो लैपटॉप कई इलेक्ट्रॉनिक समान के अलावे एक स्प्लेंडर बाइक व 2 किलोग्राम गाजा जब्त की गई है।

गिरफ्तार चोरों ने छतौनी में ही दो और चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। जिसको लेकर कांड स 271 20 व 278 ६ 20 दर्ज है। एसपी ने बताया है कि दोनों के कई और सहयोगियों की जानकारी पुलिस को मिली है जिसके नाम पते को सत्यापित करते हुए उसके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

Yuvaraj Media & Entertainment
बिहार विधानसभा चुनाव में डिजीटल प्रचार के लिए संपर्क करें:
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

युवराज न्यूज़ टुडे RNI:- BIHHIN05409 | वर्ष : 06 | अंक : 16+2 | पृष्ठ संख्या : 04 | तिथि : 31 अगस्त 2020

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई की रडार पर आए कथित दोस्त संदीप सिंह की पैदाइश बिहार की

खोज खबर

डा. राजेश अस्थाना,
एडिटर इन चीफ,
न्यूज टुडे मीडिया समूह

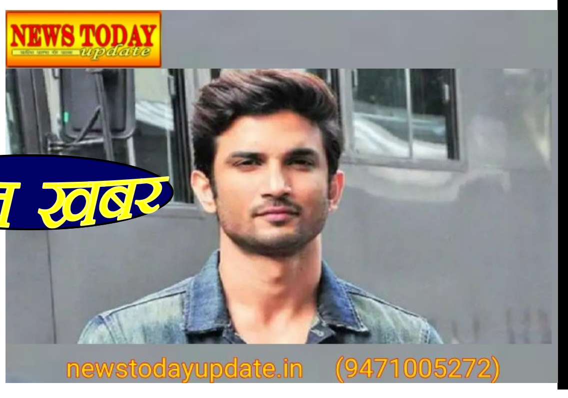

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई की रडार पर आए कथित दोस्त संदीप सिंह की पैदाइश मुजफ्फरपुर की है। उनका मकान मिठनपुरा थाने के चतुर्भुज स्थान इलाके में था। नब्बे के दशक में उनकी मां ममता शहर छोड़कर मुम्बई में जाकर बस गईं। वहां संदीप ने फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर बनाया। वर्तमान में वह एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। इस वजह से ही रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के करीब आए थे। सुशांत की मौत के बाद संदीप उनके फ्लैट पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे। मुम्बई पुलिस के साथ सुशांत की मौत के संबंध में कागजी प्रक्रिया को भी संदीप ने ही पूरा किया है। फिलहाल वह मां ममता के साथ मुम्बई के खारघार में रहते हैं। उनकी एक बहन भी है।

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित चतुर्भुज स्थान निवासी मुनव्वर हुसैन ने बताया ममता तीन भाई–बहन है। किरण व दिलीप मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं। ममता के साथ नब्बे के दशक में एक घटना हुई। इसके बाद वह शहर छोड़कर मुम्बई चली गईं। बेटा संदीप और बेटी को भी साथ ले गई थी। शहर छोड़ने के बाद अबतक मात्र एक बार शहर आयी थी। कुछ काम पूरा कर पुनः लौट गई थी। उस वक्त स्टेशन रोड के एक होटल में ठहरी थी।

मुनव्वर हुसैन ने बताया कि कई साल पहले ममता से एक बार मुम्बई के एक होटल में मुलाकात हुई थी। इस दौरान दुःख–दर्द साझा किया था। साथ ही अपनी पीड़ा भी बतायी थी। उन्होंने बताया कि उस वक्त वह एक होटल के म्यूजिकल प्रोग्राम में काम करती थी। इससे उनका परिवार चलता था। जानकारी हो कि संदीप सिंह की कुछ पढ़ाई मुजफ्फरपुर और बाकी की पढ़ाई मुम्बई में हुई। बताया जाता है कि संदीप ने एक पहचान वाले के माध्यम से बॉलीवुड में बतौर स्पॉट ब्वॉय दस्तक दी। करीब चार साल की मशक्कत के बाद खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोला। इसके बाद से अबतक चार बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। सुशांत से रिया चक्रवर्ती ने ही परिचय कराया था। रिया के करीबी में से एक हैं।

जानकारों ने बताया कि वर्ष 2000–01 में ममता मुजफ्फरपुर आई थीं। स्टेशन रोड स्थित एक होटल में करीब एक सप्ताह रुकी थी। इस दौरान जिस मकान को वह छोड़कर मुम्बई गई थी, उसे बेच दिया। इसके बाद रुपये लेकर वापस मुम्बई चली गई। फिर दोबारा मुजफ्फरपुर नहीं आई।

बताया जाता है कि वह अपनी बहन किरण और भाई दिलीप से भी कभी–कभार ही बातचीत करती है। नब्बे में मुजफ्फरपुर में अपराध चरम पर था। जमीन हड़पने का भी खेल शुरू था। इस दौरान एक अपराधी ने उस वक्त के एक दबंग के इशारे पर ममता को गोली मारी थी, लेकिन वह बच गई। मालूम हो कि इस मकान में वर्ष 2014 में एक सीआईडी के इंस्पेक्टर की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई थी।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिये दिखाई जाने वाले वेब सीरीज को लेकर क्या प्रावधान है और इसे नियंत्रित कौन करता है

ख़ास ख़बर

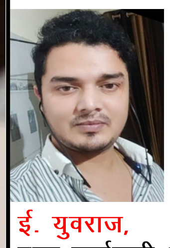

ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

अश्लील वेब सीरीज के जरिये हिंदू देवी–देवताओं और भारतीय सेना के अपमान को लेकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण विभाग को पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म के जरिये दिखाई जाने वाले वेब सीरीज को लेकर क्या प्राविधान है। इसे नियंत्रित कौन करता है। जिस तरह से फिल्मों को नियंत्रित करने के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी कोई व्यवस्था वेब सीरीज को लेकर है क्या। केंद्र को सात सितंबर तक जवाब देना है।

अश्लील वेब सीरीज के जरिये हिंदू देवी–देवताओं और भारतीय सेना के अपमान का मामला

मालूम हो, शिकायतकर्ता वाल्मीकि सकरगाए ने पांच जून को इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में एकता कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी एएलटी बालाजी सोशल मीडिया पर ट्रिपल एक्स वेब सीरीज चलाती है। वेब सीरीज में हिंदू देवी–देवताओं और भारतीय सेना का अपमान किया गया है। वेब सीरीज के जरिये अश्लीलता परोसी जा रही है। एपिसोड में दिखाया गया था कि पुरुष पात्र भारतीय सेना की वर्दी पहना होता है। एक महिला पात्र उसकी वर्दी फाड़ती है। इस अपमान से आहत होकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एकता के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआइआर को खारिज करने की मांग करते हुए एकता ने एडवोकेट विनय सराफ के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत की सीडी

20 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एकता को अंतरिम राहत दी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता से कहा था कि वे वेब सीरीज की सीडी पेश करें। बुधवार को शिकायतकर्ता ने सीडी प्रस्तुत कर दी। कोर्ट ने एकता की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रखते हुए पूछा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिये दिखाई जाने वाली वेब सीरीज को नियंत्रित करने की क्या व्यवस्था है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट बताया कि यह केंद्र का मामला है। इस पर कोर्ट ने तीन दिन में सूचना और प्रसारण विभाग को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी करने के आदेश दिए।